Development of Railways in Madhya Pradesh

362. SHRI SURENDRA SINGH THAKUR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many industrial, non-industrial and tribal areas of Madhya Pradesh are still inaccessible due to absence of railway link in these areas ;

(b) if so, whether Government are considering any proposals for development of railways linking inaccessible tribal & forest regions;

(c) Whether any proposal has been received from the Madhya Pradesh Government for construction of railways in that State ;

(d) if so, the steps taken by Government in this regard ; and

(e) What are the details of the proposals included in the Eighth five year plan for development of railways in Madhya Pradesh ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) to (c) Yes, Sir

(d) Construction of Satna-Rewa railway line is in progress and will be completed in 92-93. Surveys for new lines from Lalitpur - Khajuraho, Khajuraho--Mahoba ; Khajuraho- Satna, Rewa-Sidho-Singrauli have been taken up. Survey for Dallirajhara-Jagdalpur new BG railway line (235 km.) was carried out in 74-75. The proposed line is a single user line required by Steel Authority of India Ltd. (SAIL), for movement of iron ore to Bhillai. Cost has been advised to Ministry of Steel. Work can be taken up as and when Ministry of Steel/SAIL arrange funding for this line.

(e) Conversion of Gondia-Jabalpur, new lines from Dewas to Maksi and Guna-Etawah are likely to be completed in the 8th Plan period.

Railway Wagons for Transportation

363. SHRI ARANGIL SREEDHARAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have received a request from the Kerala Government for alloting more railway wagons for transporting rice to Kerala from other parts of the country; and

(b) if so, what steps Government have taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) Yes, Sir.

(b) Loading of foodgrains to Kerala by Food Corporation of India is more than the target for Public Distribution System in Kerala and there is no problem for wagon supply.

सवाई माधोपुर और जयपुर के मध्य बड़ी लाइन का निर्माण

364. **डा० अबरार अहमद :**
चौधरी हरि सिंह :
क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सवाई माधोपुर और जयपुर के मध्य बड़ी लाइन का निर्माण-कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि सवाई माधोपुर और जयपुर के मध्य छोटी लाइन पर चलने वाली रेलगाड़ी के मामले में भेदभाव किया जा रहा है और इन दो स्टेशनों के मध्य चलने वाली किसी भी रेलगाड़ी में डीजल इंजन नहीं हैं तथा इन रेलगाडियों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सवारी डिब्बे अत्यधिक खराब स्थिति में हैं और किसी भी रेलगाड़ी में वातानुकूलित सवारी डिब्बे नहीं हैं तथा यहां तक कि उनमें रेल-कर्मचारी भी नहीं होते हैं ;

(ग) यदि हां, तो सरकार इसमें सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ; और

(घ) क्या सरकार सवाई माधोपुर से छोटी लाइन पर कोई नई रेलगाड़ी आरम्भ करने का भी विचार रखती है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

(ख) और (ग) सवाई माधोपुर-जयपुर एक मीटर लाइन खंड है न कि छोटी लाइन खंड। इस खंड पर 2 जोड़ी फास्ट पैसेंजर और 2 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां चल रही हैं। मीटर लाइन के डीजल रेल इंजनों की अत्यधिक कमी के कारण, फिलहाल इस खंड की गाड़ियों को डीजल रेल इंजनों से चलाना व्यावहारिक नहीं है। 205/206 और 209/210 पैसेंजर गाड़ियों में वातानुकूल सवारी डिब्बों की व्यवस्था करना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है क्योंकि ये धीमी गति से चलने वाली गाड़ियां हैं। मीटर लाइन के वातानुकूल सवारी डिब्बों की कमी के कारण 9717/9718 एक्सप्रेस गाड़ियों में भी वातानुकूल सवारी डिब्बों की व्यवस्था करना व्यावहारिक नहीं है।

सभी सवारी डिब्बों का आरक्षण यात्री सुविधा समिति द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है। बहरहाल, अत्यधिक वित्तीय तंगी के कारण कतिपय गतायु सवारी डिब्बों को सेवा में रखना पड़ता है।

इस खंड पर चलने वाली गाड़ियों के आरक्षित सवारी डिब्बों में रेल कर्मचारी तैनात किये जाते हैं।

(घ) जी नहीं।

नये रेल इंजन कारखाने की स्थापना

3165. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :**
श्री राम नरेश यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रेल इंजनों के निर्माण के लिए कोई नया रेल इंजन कारखाना स्थापित न किए जाने का निर्णय लिया है क्योंकि उसके गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपे जाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेल इंजनों का निर्माण चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन और डीजल रेलइंजन कारखाना, वाराणसी में किया जाता है। इन यूनिटों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। बढ़ायी गई क्षमता से अतिरिक्त जरूरतों के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में सभी स्रोतों का उपयोग करने का प्रस्ताव है। भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड, भोपाल, जो सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, भारतीय रेलों को पहले से ही इंजनों की सप्लाई कर रहा है।

Computerised passenger reservations in the railways

366. SHRI BEKAL UTSAHI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have launched a massive plan for extending the computerised passenger reservations in the Railways, improving passenger services and making the system more customer-friendly; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) and (b) Upgradation and improvement of facilities at stations and in trains is a continuous process. Computerised reservation system is being gradually extended every year depending on reservation workload handled, subject to availability of funds. So far 36 stations have been either computerised or in the process of computerisation.

Abolishing Non-Functional Posts in the Railways

367. SHRI KAPIL VERMA :
SHRIMATI VEENA VERMA :
SHRI RAM NARESH YADAV :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal for abolishing a number of non-functional posts created with a view to ensure promotional avenues in different services; if so, what are the details thereof and likely savings; and